स्वतंत्र कुमार जे. के समक्ष

विद्यावती- याचिकाकर्ता

बनाम

गोपी राम और अन्य- प्रतीयार्थी

सी. आर. नं. 1982 का 3267

3अगस्त, 2000

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 20, नियम 1, *6 8s 7* और धारा 33।— *मुकदमा खारिज-अदालत शुल्क* के *भुगतान तक स डिक्री की* तैयारी स्थगित *-वादी कमी को पूरा करने में विफल-क्या डिक्री लेने से इनकार किया जाए-*निर्धारित *, नहीं-वादी और राज्य के* बीच *अदालत शुल्क का भुगतान-अदालत शुल्क राजस्व अधिकारियों के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।*

(मुंशी बनाम ज्ञानी, *1968 पी. एल. आर. 530,* का पालन किया गिया *)*

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के प्रावधानों का संचयी प्रभाव न्यायालय पर एक अनिवार्य दायित्व रखता है कि वह निर्णय सुनाए और यह सुनिश्चित करे कि कि एक डिक्री निर्णय के संदर्भ में तैयार की गई है। इन प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'करेगा' एक डिक्री के पारित होने के संबंध में एक निश्चित अर्थ को दर्शाती है।आम तौर पर न्यायालय वर्तमान प्रकार के मामलों में डिक्री बनाने पर रोक लगाने के लिए उचित नहीं हो सकता है।डिक्री तैयार करना निर्णय की घोषणा का एक आवश्यक परिणाम है।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान का प्रश्न न्यायालय और वादी के बीच है।वादी आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।न्यायालय कानून के अनुसार राजस्व अधिकारियों के माध्यम से न्यायालय शुल्क की वसूली का निर्देश दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आवश्यक न्यायालय शुल्क तय कर दिया गया है।

(पैरा 7)

तर्क दियाः—जी. एस. जसवाल, अधिवक्ता।

स्वतंत्र कुमार, जे.

(1) इस पुनरीक्षण याचिका में विद्वत उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सैफिडॉन द्वारा 6 नवंबर, 1982 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।वादी ने विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया था।उसने खुद को मुक़दमे की जमीन का मालिक होने का दावा किया।वादी ने प्रतिवादियों को मुक़दमे की ज़मीन से उसे बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का भी अनुरोध किया।वैकल्पिक में यह प्रार्थना की गई थी कि यदि न्यायालय का मानना है कि ज़मीन वादी के कब्जे में नहीं है तो कब्जे के लिए डिक्री भी पारित की जाए ।प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध किया और आरोपों का खंडन किया।प्रतिवादियों द्वारा यह कहा गया था कि 1 कनाल 12 मरला मापने वाला पूरा खसरा संख्या 363 वर्तमान वादी और उसके पति के संयुक्त स्वामित्व में था।इसके अलावा यह कहा गया कि यह भूमि 28 मई, 1961 के समझौते के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 को पट्टे पर दी गई थी।उन्होंने आगे मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(2) विद्वत निचली अदालत ने छह मुद्दों को तैयार किया।इस विषय से संबंधित मुद्दा नंबर 1:क्या वादी विवादित भूमि का मालिक था?विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादियों के पास वाद भूमि का कब्जा अतिक्रमणकर्ताओं के रूप में नहीं था, बल्कि वे वादी के अधीन वाद भूमि पर किरायेदार थे।निचली अदालत द्वारा तैयार किया गया मुद्दा नंबर 4 निम्नानुसार हैः—

> "4. क्या न्यायालय शुल्क और अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और यदि ऐसा है तो सही मूल्यांकन क्या होना चाहिए?"

(3) यह मुद्दा नंबर 1का जवाब प्रतिवादियों के पक्ष में और वादियों की शिकायत के खिलाफ दिया गया था।विद्वत निचली न्यायालय ने निर्धारित किया कि अदालत-शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्य 20,000 से कम नहीं था। इस प्रकार, इसने प्रतिवादी को 30 नवंबर, 1982 तक न्यायालय-शुल्क की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया।अंत में न्यायालय ने निम्नलिखित राहत दीः—

> "उपरोक्त विभिन्न मुद्दों पर मेरे निष्कर्षों को देखते हुए, वादी का मुकदमा खारिज होने योग्य है और इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, वादी द्वारा न्यायालय शुल्क की आवश्यक कमी प्रस्तुत करने के बाद डिक्री-शीट तैयार की जाएगी जैसा कि उपरोक्त अंक संख्या 4 में आदेश दिया गया है।यदि न्यायालय शुल्क की कमी निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं की जाती है, तो डिक्री-शीट तैयार किए बिना फाइल को अभिलेख कक्ष में भेज दिया जाए।"

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वत निचली अदालत एक डिक्री तैयार करने में बाधा नहीं बना सकता है, भले ही वादी न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर या उसके बाद भी न्यायालय-शुल्क की कमी को पूरा करने में विफल रहा हो।

(5) वादी की ओर से की गई प्रस्तुति में कुछ सार है।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 के तहत अदालत मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए बाध्य है और उस फैसले पर एक डिक्री तैयार की जाएगी।संहिता के आदेश 20 में इस धारा के दायरे को आगे समझाया गया है।संहिता के आदेश 20 नियम 1 में न्यायालय पर एक दायित्व रखा गया है कि मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय या तो तुरंत या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके खुली अदालत में निर्णय सुनाएगा।संहिता के आदेश 20 के नियम 6 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक डिक्री निर्णय से सहमत होगी और स्पष्ट रूप से दिए गए राहत या मुकदमे के अन्य निर्धारणों को बताएगी।नियम 7 के तहत, निर्णय के अनुरूप किसी भी समय तैयार की गई डिक्री निर्णय की घोषणा की तारीख से मानी जाएगी और न्यायालय को आगे खुद को संतुष्ट करना होगा कि डिक्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है और फिर डिक्री पर हस्ताक्षर करना होगा।

(6) संहिता के उपरोक्त प्रावधानों का संचयी प्रभाव न्यायालय पर निर्णय सुनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिक्री निर्णय के संदर्भ में तैयार की गई है।इन प्रावधानों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "करेगा" एक डिक्री के पारित होने के संबंध में एक निश्चित अर्थ को दर्शाती है।आम तौर पर न्यायालय वर्तमान प्रकार के मामलों में डिक्री बनाने पर रोक लगाने के लिए उचित नहीं हो सकता है।डिक्री तैयार करना निर्णय की घोषणा का एक आवश्यक परिणाम है।

(7) यह भी उतना ही सच है कि उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय और वादी के बीच भी है।वादी आवश्यक न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत, वादी की शिकायत आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान न करने के लिए खारिज होने के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यदि न्यायालय वादी के मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने का निर्णय देता है, तो यह न तो उचित होगा और न ही उसके अनुरूप डिक्री पारित करने से रोकने के लिए उचित होगा।हो सकता है कि न्यायालय कानून के अनुसार राजस्व अधिकारियों के माध्यम से न्यायालय शुल्क की वसूली का निर्देश दे सकता है और

इस तरह से सुनिश्चित करें कि अदालत-शुल्क चिपकाया गया है।मुंशी बनाम ज्ञानी *के* मामले में, (1) इस न्यायालय की एक पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित कियाः—

> "न्यायालय-शुल्क के मामले का निर्णय शुरुआत में ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए था और वादी को देय न्यायालय-शुल्क में यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए था, जिसमें विफल रहने पर उसका मुकदमा तुरंत खारिज किया जा सकता था।लेकिन गुण-दोष के आधार पर वादी के दावे को सुनने और उसे खारिज करने के बाद, यह व्यावहारिक रूप से वादी को उस डिक्री के खिलाफ अपील करने के लिए रोक लगा रहा है जिसमें उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया है, जब तक कि कोई डिक्री तैयार नहीं की जानी है जब तक कि वह अदालत-शुल्क में कमी को पूरा नहीं करता है।जाहिर तौर *पर आदेश,* कम *से कम कहने के लिए, अनुचित* और उचित नहीं है।वादी के विद्वान वकील ने वैलैती राम बनाम गोपी राम (ए. आई. आर. 1935 लाह) का उल्लेख किया है। 75) जिसमें न्यायाधीश टेक चंद ने नीचे दिए गए न्यायालय के इस तरह के आदेश *को* अपास्त *कर दिया और निर्देश दिया कि* यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया था, तो इसे वापस कर दिया जाए।प्रतिवादी की ओर से मोहन लालव ।नाना किशोर (1905) 28 All. 210) जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का एक निर्णय है, लेकिन वह एक ऐसा मामला था जिसमें हालांकि निचली अपीलीय अदालत में अदालत-शुल्क में कमी का पता तब चला जब उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन वह उच्च न्यायालय में एक अपील थी, लेकिन निचली अपीलीय दूसरी अदालत में अपीलकर्ता ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर भी अदालत-शुल्क की कमी को पूरा करने में विफल रहा था।वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हुआ है।स्थिति समानांतर होती अगर विद्वत विचारण न्यायाधीश ने शुरुआत में अदालत शुल्क की कमी के सवाल का फैसला किया होता, वादी को कमी को पूरा करने का अवसर दिया होता, और फिर वह ऐसा करने *में विफल रहा होता।किसी भी स्थिति में, मैं वैलैती राम के मामले में निर्णय से बंधा हुआ हूं।"*

(8) सम्मान के साथ, यह न्यायालय उपरोक्त फ़ैसले का पालन करेगा और वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करेगा और आदेश देगा कि निचली अदालत द्वारा मुद्दे संख्या 4 पर दिया गया आदेश जो कि अवश्यक अदालत शुल्क भरने क के बाद डिक्री तैयार करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए।यद्यपि निम्न न्यायालय द्वारा अन्यथा किए गए सभी निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं और न ही स्पष्ट रूप से वर्तमान संशोधन के दायरे में आ सकते हैं।

(9) परिणामस्वरूप,पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह कानून के अनुसार एक डिक्री तैयार करे और वादी को ऐसे उपचार का सहारा लेने के लिए छोड़ दे जो उसके लिए उपलब्ध हो।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय वादी से न्यायालय शुल्क की वसूली के लिए ऐसे अन्य आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा जो कानून में अनुमेय हैं, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(1)1968 PLR 530

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा.